ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, शुक्रवार 30 मई 2025

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 2 अंक 62

देश में कोरोना के 1910 एक्टिव केस, 15 मौतें:गुजरात में 1 दिन के नवजात की रिपोर्ट पॉजिटिव, 8 महीने की बच्ची ऑक्सीजन सपोर्ट पर

देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेज की संख्या शुक्रवार को 1910 पहुंच गई। गुजराज के अहमदाबाद में एक दिन के नवजात की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्चे को ICU में रखा गया है। पिछले सप्ताह बच्चे की मां भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, हालांकि अब उनकी रिपोर्ट निगेटिव है। इसके अलावा 8 महीने की एक बच्ची गुरुवार से ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वहीं, देश में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 15 हो गई है, इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में हैं। राज्य सरकार कोरोना वायरस के लिए इन्फ्लूएंजा और सांस से जुड़ी बीमारियों पर सर्वे करा रही है।

उधर केरल में एक्टिव मामले 727 हो गए हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन JN वैरिएंट LF7 के मामले आ रहे हैं। है। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग और आयुष मंत्रालय पूरी तरह सतर्क हैं और हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं।

महाराष्ट्र में 9 हजार से ज्यादा कोविड टेस्ट

महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि गुरुवार को कोविड के 79 नए मामले सामने आए। जबकि मुंबई में जनवरी 2025 से अब तक कुल 379 केस मिले हैं। जनवरी और फरवरी में एक-एक, अप्रैल में चार और मई में 373 मरीज मिले। जनवरी से अब तक राज्य में 9592 कोविड-19 टेस्ट किए गए।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को कोविड-19 के दो मामले सामने आए थे। दोनों केरल के रहने वाले हैं और श्रीनगर के गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं।

चौथी तिमाही में 7.4% की दर से बढ़ी इकोनॉमी:पूरे साल में 6.5% रही GDP; कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रिकॉर्ड 9.4% ग्रोथ

24 न्यूज अपडेट

वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ 7.4% रही है। पिछले साल की समान तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही थी। कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन के कारण जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर रही है।

वहीं पूरे साल में इकोनॉमी के 6.5% की दर से बढ़ी है। केंद्र सरकार आज यानी, 30 मई को शाम 4 बजे वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए GDP के प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किए है।

तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 6.2% रही थी

वित्त वर्ष 2024-2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में GDP ग्रोथ 6.2% रही थी। एक साल पहले की समान तिमाही (Q3 FY24) में ये 8.4% रही थी। शुक्रवार 28 फरवरी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने ये डेटा जारी किया था।

ओडिशा में इंजीनियर के घर से 2 करोड़ कैश बरामद: विजिलेंस टीम को देखकर खिड़की से नोटों के बंडल फेंके; 7 ठिकानों पर रेड जारी

ओडिशा में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक चीफ इंजीनियर के 7 ठिकानों पर रेड की। इस दौरान उसके दो घरों से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। लाखों रुपए के सोने के गहने और मंहगे कपड़े भी मिले हैं।

विजिलेंस टीम को देखते ही चीफ इंजीनियर भुवनेश्वर स्थित अपने फ्लैट की खिड़की से 500 रुपए के नोटों के बंडल फेंकने लगा था। अधिकारियों ने नोटों की गड्डी बरामद कर ली है। कैश गिनने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। नोटों की गिनती जारी है।

इंजीनियर की पहचान ओडिशा सरकार के कर्मचारी बैकुंठ नाथ सारंगी के रूप में हुई है। वह राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में काम करता है। उसके पास आय से अधिक संपत्ति होने का शक है। अधिकारियों ने बताया कि इंजीनियर के आवास और ऑफिस में तलाशी जारी है।

आधिकारिक बयान में बताया गया कि ओडिशा पुलिस की एंटी करप्शन विंग ने भुवनेश्वर, अंगुल और पुरी में चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर पर छापा मारा। उनके भुवनेश्वर स्थित फ्लैट से करीब 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए, जबकि अंगुल स्थित पैतृक आवास से 1.1 करोड़ रुपए मिले हैं।

बैकुंठ नाथ सारंगी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। अंगुल में विजिलेंस के स्पेशन जज ने उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया था, जिसके आधार पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। विजिलेंस ने अंगुल के करदागड़िया में दो मंजिला घर, भुवनेश्वर और पुरी जिले के पिपिली के सिउला में फ्लैट सहित 7 ठिकानों का पता लगाया।

इसके बाद 26 पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने सभी 7 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। टीम में आठ DSP, 12 इंस्पेक्टर और छह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शामिल थे। अंगुल में सारंगी के पैतृक घर के अलावा रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई है।

भुवनेश्वर में आरडी प्लानिंग एंड रोड स्थित चीफ इंजीनियर के ऑफिस पर तलाशी ली गई। कैश बरामद होने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें फर्श पर नोटों का ढेर पड़ा है। आसपास बैठे अधिकारियों को कैश गिनते हुए देखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट बोला- रिलेशनशिप टूटने के बाद रेप केस गलत:इससे आरोपी की छवि खराब होती है, न्याय व्यवस्था पर भी बोझ पड़ता है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में कहा, 'यदि दो वयस्कों में सहमति से बना रिश्ता बाद में टूट जाता है या दोनों के बीच दूरी आ जाती है, तो इसे शादी का झूठा वादा बताकर रेप का केस नहीं बनाया जा सकता।'

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा- ऐसे मामलों से न केवल न्याय व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, बल्कि आरोपी व्यक्ति की सामाजिक छवि को भी गंभीर नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिर्फ शादी का वादा तोड़ने को झूठा वादा नहीं माना जा सकता, जब तक कि आरोपी की तरफ से रिश्ते की शुरुआत से ही धोखाधड़ी का इरादा न हो। बेंच ने कहा कि शादी का वादा तोड़ने को झूठा वादा बताकर धारा 376 के तहत रेप का केस करना गलत है। इस सोच पर पहले भी चिंता जताई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के साथ ही महाराष्ट्र के अमोल भगवान नेहुल के खिलाफ रेप केस रद्द कर दिया। आरोपी नेहुल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उस पर दर्ज आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए आपराधिक कार्यवाही खत्म की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक मामले में कहा था कि 16 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद कोई महिला रेप का आरोप नहीं लगा सकती। सिर्फ शादी करने का वादा तोड़ने से रेप का मामला नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो जाए कि शुरुआत से ही शादी की कोई मंशा नहीं थी। महिला ने 2022 में अपने पूर्व लिवइन पार्टनर पर रेप का केस दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि 2006 में पार्टनर जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी का झांसा देकर 16 साल तक उसका शोषण किया। फिर किसी दूसरी महिला से शादी कर ली।

ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर छिड़ा नया विवाद:श्री श्री रविशंकर बोले- मेरे पास हैं शिवलिंग के अंश, शंकराचार्यों, संतों, महंतों ने किया विरोध

प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को लेकर नया विवाद छिड़ गया है। शंकराचार्यों, संतों, महंतों और शिव उपासकों ने श्री श्री रविशंकर की सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को दोबारा स्थापित करने की घोषणा का विरोध शुरू कर दिया है।

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि श्री श्री रविशंकर ने अब तक इस बारे में बात क्यों नहीं की? द्वारका शारदापीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा- ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और इसे दोबारा प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, हरिगिरि महाराज ने कहा- ज्वाला को कभी खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे दोबारा स्थापित करने का सवाल ही नहीं उठता।

शिव उपासक निजानंद स्वामी ने कहा कि 1000 साल पुराने सोमनाथ शिवलिंग के टुकड़े किसी के पास होना संभव नहीं है। सोमनाथ ट्रस्ट के ट्रस्टी पीके लाहिड़ी ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये टुकड़े मूल शिवलिंग के हैं या नहीं।

हाल ही में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर ने यह दावा कर सबका ध्यान खींचा था कि उनके पास सोमनाथ शिवलिंग के 4 हिस्से हैं। इस शिवलिंग को 1,000 साल पहले महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि शिवलिंग के ये टुकड़े उन्हें हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के दौरान मिले। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि 4 में से दो हिस्सों को सोमनाथ मंदिर में दोबारा स्थापित किया जाएगा।

श्री श्री रविशंकर कई मीडिया संस्थानों को दिए इंटरव्यू में शिवलिंग के इन हिस्सों को सोमनाथ में दोबारा स्थापित करने की बात कह चुके हैं। श्री श्री रविशंकर की इसी घोषणा पर उनकी राय जानने के लिए शंकराचार्यों और संतों-महंतों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने श्री श्री रविशंकर के दावे का कड़ा विरोध किया है।

सोना 170 सस्ता होकर 95,355 पर आया:चांदी का भाव 642 कम हुआ, 97,458 प्रति किलो बिक रही

24 न्यूज अपडेट

सोने-चांदी के दाम में आज यानी 30 मई को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 170 रुपए घटकर 95,355 रुपए पर आ गया। कल यह 95,525 रुपए प्रति 10 ग्राम था।

वहीं, चांदी की कीमत आज 642 रुपए गिरकर 97,458 रुपए रह गई। कल चांदी 98,100 रुपए किलो थी। इससे पहले सोने ने 21 अप्रैल को 99,100 और 28 मार्च को चांदी ने 1,00,934 का ऑल टाइम हाई बनाया था।

सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 पर बंद:निफ्टी 83 अंक लुढ़का, जोमैटो का शेयर 4.95% चढ़ा; सरकारी बैंकिंग शेयरों में 3% की तेजी

24 न्यूज अपडेट

हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 30 मई को सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 81,451 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 83 अंक की गिरावट रही, ये 24,751 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। जोमैटो का शेयर 4.95% चढ़ा। SBI, HDFC बैंक, LT और बजाज फिनसर्व के शेयर भी 2% ऊपर बंद हुए। HCL टेक, टेक महिंद्रा और इंफोसिस समेत 14 शेयरों में 2% तक की गिरावट रही।

निफ्टी के 50 शेयरों में से 7 में तेजी और 43 में गिरावट देखने को मिली। NSE के सरकारी बैंकों का इंडेक्स 2.88% चढ़ा। जबकि, मेटल में 1.69%, IT में 1.15% और ऑटो में 0.98% की गिरावट रही।

मस्क का मिशन मंगल रोबोटिक मिशन, 2026 में जाएगा रोबोटिक दल, हर दो साल में 2000 स्टारशिप लॉन्च करने की योजना

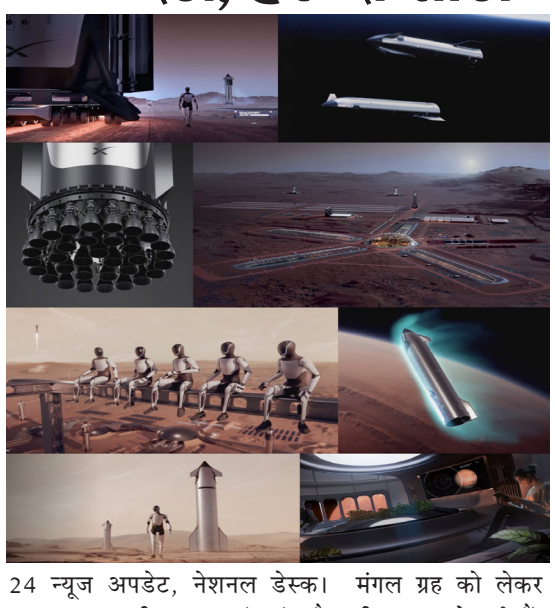

24 न्यूज अपडेट, नेशनल डेस्क। मंगल ग्रह को लेकर एलन मस्क की महत्वाकांक्षाएं और भी स्पष्ट हो गई हैं। हाल ही में SpaceX का Starship टेस्ट उड़ान के दौरान विफल हो गया, लेकिन इसके महज दो दिन बाद ही मस्क ने एक नई योजना की घोषणा कर अंतरिक्ष जगत को फिर से उत्साहित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2026 के अंत तक पहला मानवरहित Starship मिशन मंगल की ओर रवाना होगा और यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो हर दो साल में 2,000 Starship मिशन भेजे जाएंगे ताकि वहां स्थायी मानव बस्ती बसाई जा सके।

SpaceX के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर जारी एक वीडियो में मस्क ने Starship के विकास और आगामी अभियानों की विस्तृत समय-सीमा साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2026 की समयसीमा पूरी तरह Starship की तकनीकी चुनौतियों को पार करने की क्षमता पर निर्भर करेगी, खासकर इन-ऑर्बिट ईंधन भरने की प्रक्रिया, जो अब तक की सबसे जटिल बाधाओं में से एक है। 2026 का अंत खगोलीय दृष्टि से एक दुर्लभ संयोग लेकर आएगा जब पृथ्वी और मंगल के बीच सबसे कम दूरी होगी। इस "प्लैनेटरी एलाइनमेंट" की मदद से मिशन का ट्रांजिट टाइम लगभग 7 से 9 महीने तक सीमित रहेगा। यदि SpaceX इस मौके का फायदा नहीं उठा पाती, तो अगला मौका सीधे 2028 में मिलेगा। मस्क ने यह भी बताया कि पहला मिशन Tesla द्वारा बनाए गए 'Optimus' ह्यूमनॉइड रोबोट को मंगल पर ले जाएगा, जो भविष्य के मानव मिशनों की पूर्व तैयारी के रूप में कार्य करेगा। इसके बाद के चरणों में असली मानव चालक दल को भेजने की योजना है।

हालांकि, Starship की नौवीं परीक्षण उड़ान हाल ही में विफल रही थी, जिसमें उड़ान भरने के 30 मिनट बाद ईंधन रिसाव के कारण यान नियंत्रण खो बैठा और पृथ्वी पर गिरकर ध्वस्त हो गया। इससे पहले जनवरी और मार्च 2025 में हुए परीक्षण भी उड़ान के शुरुआती क्षणों में विस्फोट के कारण असफल रहे थे। इन परीक्षणों के कारण कैरीबियाई क्षेत्र में हवाई उड़ानों को भी अस्थायी रूप से डायवर्ट करना पड़ा था। इसके बावजूद, एलन मस्क असफलताओं को सीख और आगे बढ़ने का अवसर मानते हैं। उन्होंने कहा कि हर परीक्षण SpaceX को कीमती डेटा देता है और अगली उड़ानों की दिशा को और सटीक बनाता है। इस बीच, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA भी Starship पर भरोसा कर रही है। NASA का Artemis कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य 2027 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को फिर से भेजना है, Starship तकनीक पर आधारित है। मस्क के अनुसार, चंद्रमा पर मानव की वापसी मंगल पर मानव मिशन की पूर्वशर्त है।

अपनी क्षेत्र से सम्बन्धित समाचार हमारी मेल आई पर भेजें

desk24newsupdate@gmail.com

संपादकीय : सत्ता और शांति

मणिपुर में लंबे समय से शांति बहाली के प्रयास चल रहे हैं। वहां करीब दो वर्ष पहले मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव की शुरुआत के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसे संभाल पाना राज्य की तत्कालीन सरकार के लिए संभव नहीं हुआ और इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह को आखिर इस्तीफा देना पड़ा। पिछले तीन महीने से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। यों हिंसा और संघर्ष पर काबू पाने में नाकामी की वजह से पहले से ही वहां राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही थी। विडंबना यह है कि आज भी मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव को खत्म करना और सर्वसम्मति से समाधान तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सका है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि वहां नई सरकार के गठन के लिए जो कवायद शुरू हुई है और किन्हीं हालात में यह संभव हो पाता है, तो क्या इससे मणिपुर की मौजूदा समस्या का कोई ठोस हल निकल सकेगा और क्या वहां हिंसा और टकराव का दौर खत्म हो पाएगा। गौरतलब है कि मणिपुर में राजग के दस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर चौवालीस विधायकों के समर्थन का हवाला देते हुए सरकार गठन की मांग की है। विधायकों के इस समूह ने सरकार गठन को जनता की इच्छा बताया । लेकिन अगर इन विधायकों के साथ कुकी समुदाय के दस विधायक नहीं हैं, तो ऐसे में इस समूह के पास राज्य की सबसे मुख्य समस्या से पार पाने के लिए क्या योजना और दृष्टि है। राज्य में नई सरकार बनाने के पक्ष में भाजपा स राजग के कई विधायक जरूर हैं, लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब भी सरकार के बनाने के दावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर में निकट भविष्य में राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने की भी खबर आई है। ऐसे में नई सरकार के गठन की मांग के धरातल पर उतरने की उम्मीद फिलहाल आगे की बात लगती है । इसके बावजूद यह सच है कि मणिपुर में शांति बहाली और सामुदायिक टकराव के कारणों को दूर कर दूरगामी हल निकलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही संभव है। हालांकि मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर चाहे जो भी कोशिशें चल रही हों, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि वहां आम जनजीवन जिस अस्थिरता और आए दिन हिंसक सामुदायिक टकराव से दो-चार है, उसका कोई ठोस समाधान निकाला जाए। मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के सवाल पर दो वर्ष पहले जिस हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसमें अब तक ढाई सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आज भी आए दिन गोलीबारी या हिंसक घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ऐसी खाई बन गई है, जिसे पार्ट बिना किसी दीर्घकालिक हल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मगर दोनों समुदायों में परस्पर विश्वास बहाली को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जो संवाद का कोई सार्थक पुल तैयार करे और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हो । आज भी अगर मणिपुर का आम जनजीवन अस्थिर है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है ? जाहिर है, नई सरकार के गठन के प्रयासों के समांतर जरूरत इस बात की है कि वहां संघर्षरत समुदायों के बीच विश्वास और संवाद कायम किया जाए।

जिम्मेदारी के बजाय

संसदीय समितियों की बैठकों में सांसदों की कम भागीदारी वास्तव में चिंता का विषय है। लोग इस उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं कि उनके बुनियादी हितों की बात वहां सही तरीके से रखी जाएगी। मगर लोकसभा की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों से पता चलता है। कि निचले सदन की सोलह स्थायी समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति औसतन महज साठ फीसद रही है। संसदीय समितियों की बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है और जरूरी सुधारों का खाका तैयार किया जाता है । इसका मकसद सरकारी योजनाओं और नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करना और सभी पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाना होता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि कई सांसदों के भीतर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई अवसरों पर संसदीय समिति और संसद की कार्यवाही में सांसदों की सहभागिता के महत्त्व को रेखांकित कर चुके हैं। मगर संसद की स्थायी समितियों में सांसदों के गैरहाजिर रहने का सिलसिला हैरान करने वाला है। गौरतलब है कि संसद में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अलग-अलग स्थायी समितियां होती हैं। कई बार सरकार की ओर से तैयार की गई योजनाओं और नई नीतियों व कानूनों का मसविदा इन समितियों के पास विचार के लिए आता है। आमतौर पर विपक्षी दलों की यह मांग रहती है कि कोई भी विधेयक सदन में पेश किए जाने से पहले विचार-विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए। अफसोस की बात है कि इन समितियों की बैठकों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का अहसास सांसदों में कम ही नजर आता है। अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि इस वर्ष बीस मई को विदेश मंत्रलय से संबद्ध स्थायी समिति की बैठक में केवल तेरह सदस्य उपस्थित थे, जबकि 16 मई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विषय पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से संबद्ध समिति की बैठक में केवल बारह सदस्य मौजूद थे। ऐसे में सांसदों से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि वे संसद में तय किए जाने वाले नियम- कायदों या बनने वाली व्यवस्था में जनता के हित में संसदीय समितियों में होने वाले विमर्श के तहत सक्रिय भागीदारी करें।

सरकारी बैठक में 'समाजसेवी' की विशेष उपस्थिति ने खड़े किए कई सवाल, क्या बदल रही है प्रशासनिक बैठकों की परंपरा?

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। जल स्वावलंबन पखवाड़े और मानसून पूर्व बाढ़ प्रबंधन तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलक्ट्रेट सभागार में एक अहम संभाग स्तरीय सरकारी बैठक आयोजित हुई। बैठक में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, संभागीय आयुक्त, आईजी, सभी जिले के कलक्टर, विधायकगण और विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक का उद्देश्य बेहद गंभीर था-जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और आगामी मानसून में संभावित आपदाओं से निपटने की रणनीति तय करना। लेकिन इस गहन प्रशासनिक बैठक में उदयपुर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष की 'समाजसेवी' के रूप में उपस्थिति ने कई हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है। जब राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, आईएएस-आईपीएस और विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारी किसी रणनीतिक और संवेदनशील सरकारी बैठक में शामिल हों, तो वहां राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की गैर सरकारी हैसियत से मौजूदगी सवाल खड़े करती है। ऐसे समाजसेवी, जो किसी निर्वाचित निकाय का हिस्सा नहीं हैं, जिनके पास न तो कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी है और न ही जवाबदेही है, उनकी उपस्थिति क्या बैठक की शुचिता और डेकोरम को प्रभावित नहीं करती है यह चर्चा का विषय है?

बैठक में मीडिया तक सीमित, पर 'समाजसेवी' अंदर

गौरतलब है कि इस बैठक में पत्रकारों को भी केवल फोटो और कुछ फुटेज तक की सीमित अनुमति दी गई थी। मीडिया को बाहर रखकर बैठक की गोपनीयता बनाए रखना यदि प्रशासन की प्राथमिकता थी, तो फिर गोपनीय सरकारी चर्चा में 'समाजसेवी' के नाम पर कैसे प्रवेश मिला? क्या यह प्रशासन और राजनीति के एक नए समीकरण की शुरुआत है?

क्या अब सरकारी बैठकों में दिखेंगे 'राजनीतिक समाजसेवी'? बैठक में जल संरक्षण के साथ-साथ बाढ़ प्रबंधन, पौधारोपण, अतिक्रमण हटाने जैसे विषयों पर विस्तृत योजनाएं बनीं। स्वाभाविक है कि ऐसी बैठकों में नीतिगत दिशा तय होती है और कई ऐसे तथ्य साझा होते हैं जो आम जनता या गैर-जवाबदेह व्यक्तियों के लिए नहीं होते। ऐसे में इस उपस्थिति को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब प्रशासनिक अधिकारियों को राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के प्रति भी जवाबदेह होना होगा? सरकारी बैठकों में पारदर्शिता और जवाबदेही की उम्मीद हमेशा से रहती है, लेकिन यदि राजनीतिक प्रभाव के चलते किसी प्रतिनिधि को 'समाजसेवी' के रूप में अंदर आने की छूट मिलती है, तो यह न केवल बाकी राजनीतिक दलों बल्कि पूरे लोकतांत्रिक प्रशासनिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है।

क्या कहता है सिस्टम?

सवाल यह भी उठता है कि यदि बैठक 'सार्वजनिक' थी, तो अन्य समाजसेवियों, स्वयंसेवी संगठनों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को भी क्यों नहीं बुलाया गया? और यदि बैठक सरकारी एवं गोपनीय थी, तो उस व्यवस्था को भेदकर एक राजनीतिक प्रतिनिधि कैसे भीतर पहुंचे? इसमें सभी दलों के सभी प्रतिनिधि बतौर समाजसेवी मौजूद होते तो बैलेंसिंग एकट दिखाई देता। यह एक साधारण बात नहीं है। यह एक संकेत है प्रशासनिक कार्यप्रणाली में धीरे-धीरे राजनीतिक प्रभाव की बढ़ती पैठ का। यदि यही चलन बना रहा तो आने वाले समय में ऐसी सरकारी बैठकों की विश्वसनीयता, गंभीरता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगना तय है। क्या सरकार और प्रशासन इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाएंगे? या फिर यह नया 'नॉर्मल' बनने जा रहा है?

नोट : यह समाचार सरकारी तथ्यों के इनपुट के आधार पर बनाया गया है। इसमें किसी भी पक्ष का कोई वर्शन प्राप्त होने पर समाचार का पुनर्गठन, पुनर्लेखन किया जा सकता है।

मानसून का प्रवेश द्वार होने से जल स्वावलंबन में उदयपुर संभाग की खास भूमिका : जल संसाधन मंत्री

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 30 मई। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने कहा कि जल संरक्षण की दृष्टि से उदयपुर रियासत काल से सजग है। यहां सदियों पूर्व बनी जल संरचनाएं आज भी पूरे विश्व को प्रेरित करती हैं। उदयपुर संभाग मानसून का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आगामी 5 जून से प्रारंभ होने वाले जल स्वावलंबन पखवाड़े में उदयपुर संभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

जल संसाधन मंत्री श्री रावत शुक्रवार अपराह्न कलक्ट्रेट सभागार में जल स्वावलंबन पखवाड़े और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संभागीय स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, संभागीय आयुक्त सुश्री प्रज्ञा केवलरमानी, आईजी राजेश मीणा, जिला कलक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही चित्तौडगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिलों के जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

श्री रावत ने कहा कि राजस्थान सरकार जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर सजग और संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार राज्यभर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत 5 जून से 20 जून तक प्रदेश भर में जल स्वावलंबन पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर किया जाएगा।

मंत्री श्री रावत ने बताया कि यह पखवाड़ा केवल सरकारी औपचारिकता न होकर जनभागीदारी से संचालित एक व्यापक सामाजिक अभियान होगा। इसके तहत जल स्रोतों का संरक्षण, परंपरागत जल संचयन प्रणाली का पुनर्जीवन, जलाशयों की सफाई, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन, पौधारोपण, श्रमदान और जनजागृति जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, पंचायत, स्वयंसेवी संगठन, युवा और किसान समूहों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में जल की प्रत्येक बूंद का महत्व है, और ऐसे में इस पखवाड़े के माध्यम से जन-जन को जल संरक्षण की दिशा में जागरूक करना सरकार की प्राथमिकता है।

जिले वार तैयारियों की ली जानकारी, दिए निर्देश

मंत्री श्री रावत ने उदयपुर सहित संभाग के सभी जिलों से जल स्वावलंबन पखवाड़े के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने अभियान में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने, हर विधानसभा स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वृहद् कार्यक्रम करने, हर पंचायत में जल संरचना पर जल पूजन सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएसआर से भी अधिक से अधिक जल संरक्षण व पौधारोपण के कार्य कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 5 जून से पूर्व वातावरण निर्माण के लिए रैली, कलश यात्रा, प्रभात फेरी जैसी गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए।

हरियाळो राजस्थान की भी जानी तैयारियां

मंत्री श्री रावत ने संभाग के सभी जिला कलक्टर्स से आगामी वर्षा ऋतु में हरियाळो राजस्थान के तहत किए जाने वाले पौधरोपण की कार्ययोजना पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए पौधरोपण कराने तथा पौधों की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

जल प्रवाह मार्गों से हटाएं अतिक्रमण

मंत्री श्री रावत ने आगामी मानसून के मद्देनजर बाढ़ प्रबंधन तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने जिलेवार बढ़े जल स्त्रोतों, अतिवृष्टि की स्थिति में जल भराव वाले स्थलों को लेकर तैयार एक्शन प्लान पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने ग्राम स्तर तक जल प्रवाह मार्गों, नदी, तालाबों में अतिक्रमण चिन्हित कराकर उन्हें जल्द से जल्द हटवाने के भी निर्देश दिए।

यह भी रहे मौजूद

बैठक में जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त छोगाराम देवासी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अतिरिक्त आयुक्त गीतेशश्री मालवीया, समाजसेवी गजपालसिंह, उप वन संरक्षक अजय चित्तौड़ा, मुकेश सैनी, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज जैन, पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता रविन्द्र चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।

डाकघर योजनाओं और आधार सुविधा के लिए जिला स्तरीय शिविर 31 को

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 30 मई। उदयपुर प्रधान डाकघर में 31 मई, शनिवार को जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं के साथ आधार कार्ड नामांकन और सुधार करवा सकते हैं। प्रवर अधीक्षक डाक मण्डल उदयपुर ने बताया कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों को डाकघर की योजनाओं के बारे में जानकारी देना तथा आधार कार्ड संबंधित कार्रवाई एक ही स्थान पर पूर्ण करना है। शिविर में सुकन्या समृद्धि योजनाए वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाए आवर्ती जमा खाताए सावधि जमा खाताए पीपीएफए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक सेवाओं के साथ ही आधार नामांकन और सुधार सुविधा उपलब्ध रहेंगी। आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि साथ लाएं।

उदयपुर से जुड़ी तीन प्रमुख रेलसेवाओं में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी, गर्मी में यात्रियों को बड़ी राहत

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा उदयपुर से संबंधित तीन प्रमुख रेलसेवाओं में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है। इससे यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। उदयपुर से जुड़ी रेलसेवाओं में बढ़ोतरी इस प्रकार हैः

गाड़ी संख्या 20473/20474 (दिल्ली सराय - उदयपुर सिटी - दिल्ली सराय): दिल्ली सराय से 1 जून से 30 जून 2025 तक तथा उदयपुर सिटी से 2 जून से 1 जुलाई 2025 तक – 1 सेकंड एसी और 2 थर्ड एसी श्रेणी के डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी।

गाड़ी संख्या 12991/12992 (उदयपुर सिटी - जयपुर - उदयपुर सिटी): 1 जून से 30 जून 2025 तक – 2 द्वितीय कुर्सीयान और 1 साधारण श्रेणी डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी।

गाड़ी संख्या 09721/09722 (जयपुर - उदयपुर सिटी - जयपुर): जयपुर से 1 जून से 30 जून 2025 तक एवं उदयपुर सिटी से 2 जून से 1 जुलाई 2025 तक – 1 साधारण श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी।

गाड़ी संख्या 20987/20988 (उदयपुर सिटी - असारवा - उदयपुर सिटी): उदयपुर सिटी से 1 जून से 30 जून 2025 तक एवं असारवा से 2 जून से 1 जुलाई 2025 तक – 1 साधारण श्रेणी डिब्बे की अस्थाई बढ़ोतरी।

अन्य प्रमुख रेलसेवाओं में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी: उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा उदयपुर के अलावा बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर, मदार, जोधपुर, इंदौर, भगत की कोठी, साबरमती, जैसलमेर और सियालदाह सहित कुल 47 जोड़ी रेलसेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के कुल 120 डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की जा रही है। बीकानेर-दिल्ली सराय, बीकानेर-दादर, अजमेर-अमृतसर, मदार-कोलकाता, अजमेर-दिल्ली जनशताब्दी, जयपुर-दिल्ली कैंट, जोधपुर-इंदौर, इंदौर-भगत की कोठी, जोधपुर-वाराणसी सिटी, श्रीगंगानगर-अंबाला, बीकानेर-मिरज, इत्यादि।

उदयपुर सिटी-फारबिसगंज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में 4 ट्रिप का विस्तार, यात्रियों को राहत

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और यात्री भार को देखते हुए उदयपुर सिटी से फारबिसगंज के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि में चार अतिरिक्त ट्रिप का विस्तार करने का निर्णय लिया है। यह फैसला गर्मी के मौसम में बढ़ती यात्री भीड़ को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 09623 (उदयपुर सिटी-फारबिसगंज साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन) की संचालन अवधि में 3 जून 2025 से 24 जून 2025 तक चार ट्रिप का विस्तार किया गया है। इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 09624 (फारबिसगंज-उदयपुर सिटी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन) की संचालन अवधि में 5 जून 2025 से 26 जून 2025 तक चार ट्रिप बढ़ाई गई हैं। समय व ठहराव में कोई बदलाव नहीं रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस स्पेशल ट्रेन की समय-सारणी और पूर्व निर्धारित ठहराव यथावत रहेंगे। यात्रियों को पूर्व में जारी समय के अनुसार ही यात्रा करनी होगी। इस विस्तार से खासकर उन यात्रियों को लाभ मिलेगा जो बिहार के फारबिसगंज से राजस्थान के उदयपुर के बीच आवागमन करते हैं। परीक्षा, अवकाश और पर्यटन सीजन में यह ट्रेन यात्रियों के लिए राहत का माध्यम बनेगी।

शताब्दी बस से 54 किलो डोडा चूरा जब्तः डिग्गी में छिपाकर ले जाया जा रहा था नशा, बांसवाड़ा से जयपुर भेजी जा रही थी खेप

24 न्यूज अपडेट

प्रतापगढ़। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने नशे की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी शताब्दी बस से 54.180 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। यह अवैध मादक पदार्थ बांसवाड़ा से जयपुर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई चेतक टोल प्लाजा सिद्धपुरा (जिला प्रतापगढ़) के पास की गई, जहां CBN टीम ने बस को रुकवाकर तलाशी ली। बस की डिग्गी में रखे गए दो संदिग्ध पार्सल बैग से भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि CBN की कोटा सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लक्ष्मी शताब्दी बस से मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। इसके बाद टीम ने 28 मई को सक्रिय निगरानी करते हुए बस को रोका और तलाशी में यह नशे की खेप पकड़ी। फिलहाल डोडा चूरा और बस को जब्त कर लिया गया है तथा मामले की गहन जांच की जा रही है। तस्करों की पहचान और नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ व तकनीकी जांच जारी है।

डूंगरपुर में शराब की तस्करी नाकामः कार से 35 कार्टन अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर फरार

24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। मालमाथा गांव के पास गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर शराब तस्कर शराब से भरी कार मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने कार से राजस्थान निर्मित शराब के 35 कार्टन बरामद कर तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया है। बिछीवाड़ा थाने के एएसआई गजराज सिंह ने बताया कि वे हेड कांस्टेबल लोकेंद्र सिंह, तुलसीराम, कांस्टेबल हर्षित और दिनेश के साथ मालमाथा गांव की ओर गश्त पर थे। इसी दौरान एक कार ने पुलिस वाहन को देखकर अचानक दिशा बदली और रॉन्ग साइड में भागने लगी। कार से दो व्यक्ति उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार को जब्त कर उसकी तलाशी ली, जिसमें राजस्थान निर्मित अवैध शराब के 35 कार्टन पाए गए। पुलिस ने कार को थाने लाकर जब्त कर लिया है और फरार दोनों तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी, जहां शराबबंदी लागू है।

अंकिता भंडारी हत्याकांडः भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट का फैसला 2 साल 8 महीने बाद आया

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, नेशनल डेस्क। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पुलकित के साथ-साथ रिसॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता को भी दोषी करार दिया गया है। अदालत ने तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला घटना के लगभग दो साल आठ महीने बाद सुनाया गया है। फैसले से पहले कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जुटी थी। बड़ी संख्या में लोग अंकिता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए बैनर-पोस्टर लेकर पहुंचे थे। हालात को देखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया था। इस दौरान अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने न्यायालय से दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील करते हुए कहा था कि जिन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी की जान ली, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक लापता हो गई थी। वह ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी। उसकी गुमशुदगी के बाद परिजनों ने रिसॉर्ट पहुंचकर पूछताछ की और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकिता पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव बना रहा था, जिसका विरोध करने पर पुलकित ने अपने दो कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का देकर मार डाला।

घटना का खुलासा सीसीटीवी फुटेज और रिसॉर्ट कर्मचारियों की गवाही से हुआ, जिसमें स्पष्ट हुआ कि अंकिता तीनों के साथ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। वहीं, अंकिता का शव छह दिन बाद चीला नहर से SDRF टीम ने बरामद किया।

हत्या के बाद लोगों का आक्रोश इस कदर बढ़ा कि उन्होंने पुलकित आर्य के रिसॉर्ट को आग के हवाले कर दिया। भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी पर हमला किया गया। जनदबाव को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT गठित की और पुलकित के रिसॉर्ट को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया। भाजपा ने भी तत्काल प्रभाव से विनोद आर्य और उनके बेटे अंकित आर्य को पार्टी और सभी पदों से निष्कासित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेशः NEET PG परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को NEET PG 2025 परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला छात्रों द्वारा दाखिल उस याचिका के आधार पर आया जिसमें दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने पर डिफिकल्टी लेवल और नॉर्मलाइजेशन के कारण असमान मूल्यांकन की शिकायत की गई थी। छात्रों का कहना था कि एक-एक नंबर के आधार पर पीजी स्ट्रीम तय होती है, ऐसे में दो शिफ्ट में परीक्षा होना अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि यदि परीक्षा केंद्रों या समय में कोई व्यावहारिक दिक्कत हो तो परीक्षा एजेंसी समय विस्तार के लिए आवेदन कर सकती है। परीक्षा 15 जून को निर्धारित, एडमिट कार्ड 2 जून से NEET PG परीक्षा 15 जून 2025 को प्रस्तावित है और इसके एडमिट कार्ड 2 जून को जारी होंगे। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) से कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और समानता के साथ होनी चाहिए। साथ ही यह भी पूछा कि जब NEET UG जैसी बड़ी परीक्षा एक शिफ्ट में हो सकती है, तो PG में ऐसा क्यों नहीं?

क्या कहा NBEMS ने

NBEMS ने दलील दी कि यह एक ऑनलाइन परीक्षा है और सीमित संख्या में केंद्र उपलब्ध हैं। बोर्ड के अनुसार, सभी तकनीकी और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दो शिफ्ट में परीक्षा कराना ही व्यावहारिक समाधान था। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "दो अलग-अलग प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर कभी एक जैसा नहीं हो सकता।" इसलिए एक ही शिफ्ट में परीक्षा अनिवार्य होगी। छात्रों ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा की पारदर्शिता और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर याचिका दाखिल की थी। उनकी मांग थी कि प्रश्न पत्र और उत्तर सार्वजनिक किए जाएं ताकि वे अपने परिणाम का सही आकलन कर सकें। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में अलग-अलग शिफ्ट के पेपर के औसत अंकों के आधार पर कुछ छात्रों के अंक घटते या बढ़ते हैं, जिससे फाइनल मेरिट प्रभावित होती है। छात्र इसे अनुचित मूल्यांकन मानते हैं।

NEET PG में हर साल दो लाख से अधिक उम्मीदवार, 52,000 सीटों पर होता है प्रवेश

देशभर में लगभग 52,000 पीजी सीटों के लिए हर साल दो लाख से अधिक MBBS स्नातक NEET PG में शामिल होते हैं। पिछले वर्ष यह परीक्षा पहली बार दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई।

राजस्थानः पांचवीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित, 97.47% रहा परिणाम, लड़कियां लड़कों से आगे

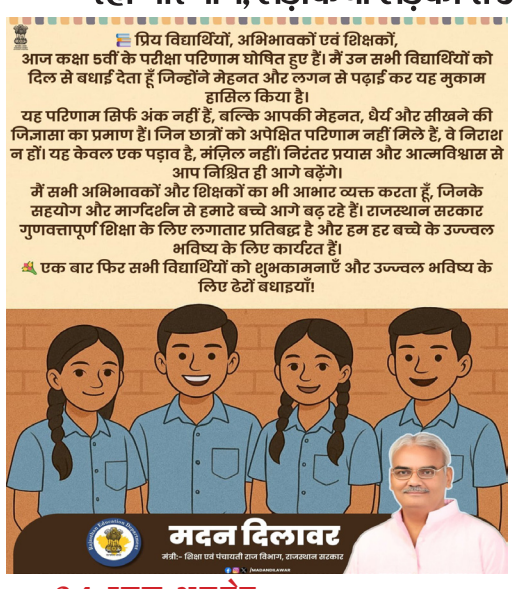

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने शुक्रवार दोपहर कक्षा 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार कुल 97.47 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। छात्राओं ने एक बार फिर छात्रों को पीछे छोड़ा है। छात्राओं का परिणाम 97.66% जबकि छात्रों का 97.29% रहा। जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में दोपहर 12:30 बजे परिणाम की घोषणा की गई। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में परिणाम को सार्वजनिक किया गया। कुल 13.30 लाख छात्रों ने दी परीक्षा इस वर्ष कुल 13,30,190 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 12,96,495 छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए। इस बार का रिजल्ट पिछले वर्ष से 0.41% अधिक रहा। परीक्षा का आयोजन 7 से 17 अप्रैल तक किया गया था। कोई छात्र फेल नहीं पांचवीं बोर्ड में कोई भी छात्र फेल नहीं किया गया है। हालांकि जिन छात्रों को 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त हुए हैं, उन्हें पुनः परीक्षा देनी होगी। ग्रेड सिस्टम के आधार पर मूल्यांकन परीक्षा परिणाम ग्रेड सिस्टम के आधार पर घोषित किया गया, जिसमें A, B, C, D और E ग्रेड शामिल हैं। E ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। यदि वे दोबारा भी पास नहीं होते हैं, तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन फेल विषयों को पुनः पढ़ना होगा। छात्र और अभिभावक 5वीं बोर्ड का परिणाम ऑनलाइन निम्नलिखित वेबसाइट्स पर देख सकते हैंः rajshaladarpan.rajasthan.gov.in rajpsp.nic.in रिजल्ट देखने के लिए ज़रूरी विवरणः रोल नंबर जिला एप्लिकेशन नंबर या स्कूल कोड/पीएसपी कोड जानकारी भरने के बाद छात्र अपना रिजल्ट डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

द्वारका के 21 द्वीपों पर 28 जुलाई तक प्रवेश प्रतिबंधितः सुरक्षा कारणों से प्रशासन सख्त, अब लेनी होगी पूर्व अनुमति

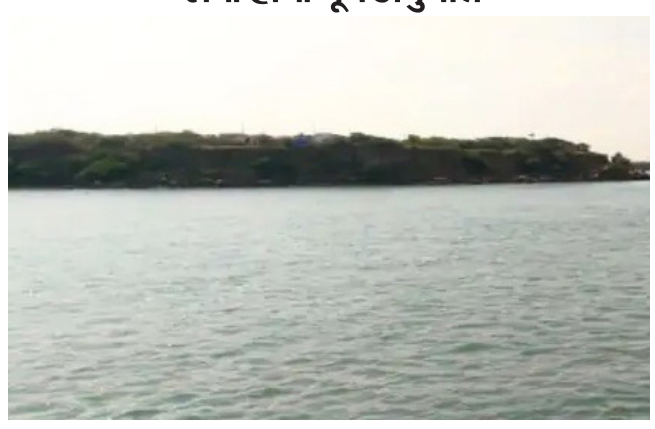

24 न्यूज अपडेट

द्वारका। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिले के 21 निर्जन द्वीपों पर 30 मई से 28 जुलाई 2025 तक जन-सामान्य के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया है और इसका उल्लंघन कानूनन दंडनीय होगा। आदेश के अनुसार इन द्वीपों में प्रवेश करने के लिए संबंधित प्रांतीय अधिकारी अथवा उप-विभागीय मजिस्ट्रेट से पूर्व लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह निर्णय द्वीपों की भौगोलिक संवेदनशीलता, असामाजिक तत्वों की संभावित गतिविधियां, और आतंकी खतरे को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 24 में से 21 द्वीप रहेंगे प्रतिबंधित देवभूमि द्वारका जिले में कुल 24 द्वीप हैं, जिनमें से केवल दो द्वीपों पर ही मानव बस्ती है। नरारा द्वीप को 2016 से कुछ शर्तों के अधीन परमिट से छूट प्राप्त है, इसलिए वहां विशेष परिस्थितियों में आमद-रफ्त बनी रह सकती है। शेष द्वीप पूरी तरह निर्जन हैं लेकिन वहां धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहां आमतौर पर श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार इन द्वीपों का दुर्गम भूगोल और सीमावर्ती स्थिति उन्हें तस्करी, गैरकानूनी गतिविधियों और राष्ट्रविरोधी तत्वों की आवाजाही के लिए संवेदनशील बनाता है। आतंकी संगठनों द्वारा रणनीतिक स्थानों पर हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर यह आदेश लागू किया गया। ये हैं वे 21 द्वीप, जहां प्रवेश निषेध प्रतिबंधित द्वीपों में धानी, गांधीयोकडो, कालुभर, रोजी, पानेरो, गड्डू, सानबेली, खिमारोघाट, आशाबापीर, भैदर, चांक, धबधबो, दीवडी, सामियाणी, नोरू, मान मरुडी, लेफा मरुडी, लंधा मरुडी, कोठानु जंगल, खारा मीठा चुश्ना और कुडचली शामिल हैं।

जयपुर की दो कोर्टों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच के बाद झूठी साबित हुई

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट,स्टेट डेस्क। राजधानी जयपुर एक बार फिर बम धमाके की धमकी से दहल उठी है। शुक्रवार सुबह गांधी नगर स्थित फैमिली कोर्ट और बनीपार्क स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इमारत को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। दोनों कोर्ट परिसरों को तत्काल खाली करवाया गया और बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और एटीएस टीमों की मौजूदगी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि फैमिली कोर्ट क्रम-4 की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ, जिसमें दोनों कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। ईमेल की सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर दोनों स्थलों को सील कर दिया और व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। हालांकि अब तक तलाशी अभियान में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर मिनी सचिवालय परिसर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। इससे पहले भी जयपुर में एसएमएस स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन सहित कई सार्वजनिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, जो जांच के बाद झूठी साबित हुई थीं। फिलहाल, पुलिस धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है और साइबर सेल इसकी गहराई से जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे शहर में सतर्कता बढ़ा दी है और संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है।

आयकर विभाग में अफसरों के बीच टकराव ने ली हिंसक रूपः डिप्टी कमिश्नर पर जॉइंट कमिश्नर ने किया हमला, गंभीर घायल

24 न्यूज अपडेट

लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित आयकर विभाग के कार्यालय में गुरुवार को उच्च अधिकारियों के बीच पुरानी रंजिश एक हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग पर जॉइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल अधिकारी को तत्काल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। एफआईआर के अनुसार, यह विवाद फरवरी 2025 में हुए एक विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान शुरू हुआ था। योगेंद्र मिश्रा ने उस समय जबरन टीम में शामिल होने और कप्तान बनाए जाने की मांग की थी। विरोध होने पर उन्होंने खिलाड़ियों को कथित तौर पर धमकाया, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध कई शिकायतें दर्ज हुईं। इसी के चलते उनका लखनऊ से उत्तराखंड तबादला कर दिया गया था। गालियां, गिलास से हमला और फिर गला दबाया गुरुवार दोपहर तीन बजे के करीब जब गर्ग अपने ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, तभी मिश्रा वहां पहुंचे और उच्च स्वर में गालियां देने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफर और विभागीय कार्रवाई के पीछे गर्ग की भूमिका है। आरोप है कि मिश्रा ने टेबल पर रखा कांच का गिलास उठाकर गर्ग की ओर फेंका, और फिर उनके पास जाकर गर्दन पर वार किया तथा गला दबाने की कोशिश की। उन्होंने गर्ग को मुक्के मारे और जूतों से प्राइवेट पार्ट पर हमला किया, जिससे गर्ग को गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद गर्ग बेहोश हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। एफआईआर में यह भी बताया गया है कि मिश्रा ने खिलाड़ियों को व्हाट्सऐप पर आपत्तिजनक भाषा में धमकियां दी थीं। यहां तक कि एक खिलाड़ी को नशीले पदार्थ के झूठे केस में फंसाने तक की चेतावनी दी गई थी। इस प्रकार की कुल 12 शिकायतें विभाग में पहुंचीं थीं, जिनकी जांच गर्ग के निर्देश पर प्रारंभ हुई थी। हमले के दौरान मौजूद थे वरिष्ठ अधिकारी घटना के समय वरिष्ठ अधिकारी ऋचा रस्तोगी और शौर्य शाश्वत शुक्ला भी कमरे में मौजूद थे। शुक्ला ने गर्ग को बचाने का प्रयास किया। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर घायल अधिकारी को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

पुलिस कार्रवाई व जांच

ACP हजरतगंज विकास जायसवाल के अनुसार, आरोपी योगेंद्र मिश्रा के विरुद्ध धारा 307 (हत्या का प्रयास) और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच के बाद कहा गया है कि यह हमला पूर्व नियोजित और प्रतिशोध से प्रेरित हो सकता है। घटना के बाद आयकर विभाग के अफसरों में सन्नाटा पसरा है। किसी भी अधिकारी ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है।

एक अकेला सब पर भारी : खाद फैक्ट्रियों पर मंत्री किरोड़ी मीणा ने फिर डाले छापे, कूदकर, ताले लगाकर भागे कर्मचारी, 5 फैक्ट्रियां सीज, 34 की जांच

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, किशनगढ़। अगर एक मंत्री ठान लें कि मिलावटखोरों की खैर लेनी है तो पूरा का पूरा सिस्टम हिला सकता है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दो दिन में भ्रष्ट तंत्र का खाद-पानी रोक दिया। बंदी लेने वाले अधिकारियों, नेताओं से लेकर मिलावटखोरों तक के होंश उड़े हुए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन सख्त कार्रवाई की। किशनगढ़ क्षेत्र के डींडवाड़ा, बांदरसिंदरी और चौसला गांवों में फैक्ट्रियों पर अचानक पहुंचे मंत्री को देखकर कई कर्मचारी फैक्ट्रियों में ताला लगाकर फरार हो गए। इस दौरान अधिकारियों की टीम ने मौके पर जांच करते हुए 5 फैक्ट्रियों को सीज कर दिया। गुरुवार को की गई कार्रवाई के बाद मंत्री मीणा किशनगढ़ में ही आरके मार्बल के गेस्ट हाउस में रुके थे। शुक्रवार सुबह उन्होंने फिर निरीक्षण शुरू किया। पहले डींडवाड़ा की राधिका एग्रो फैक्ट्री, फिर बांदरसिंदरी की एक अन्य फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसके बाद जब मंत्री चोसला गांव पहुंचे, तो वहां स्थित श्री एग्रो फैक्ट्री के कर्मचारी खाद बाहर फेंक कर फैक्ट्री बंद कर भाग निकले। मंत्री ने अधिकारियों को तत्काल फैक्ट्री खोलकर जांच के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने 5 फैक्ट्रियों को किया सीज

जयपुर और अजमेर के कृषि विभाग के अधिकारियों ने किशनगढ़ क्षेत्र के उदयपुरकलां और टीकावड़ा गांवों में भी कार्रवाई की। अजमेर जिले की आत्मा परियोजना की प्रोजेक्ट डायरेक्टर उषा चितारा ने बताया कि शुक्रवार को भूमि एग्रोटेक्स, गोवर्धन एग्रो और टीकावड़ा की दो अन्य फैक्ट्रियों को सीज किया गया है। साथ ही टेम्पो, जेसीबी और ट्रेलर जैसी मशीनें जब्त की गईं।

अब तक 34 फैक्ट्रियां जांच के घेरे में

कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर (फर्टिलाइजर्स) नवलकिशोर मीणा ने बताया कि किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की 34 फैक्ट्रियों को जांच के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें से कुछ फैक्ट्रियों से उत्तर भारत के कई राज्यों दृ हरियाणा, पंजाब, बिहार तक नकली उर्वरक की आपूर्ति की जा रही थी, इसकी प्राथमिक जानकारी सामने आई है।

गुरुवार को जिन फैक्ट्रियों पर की गई थी जांच

गुरुवार को मंत्री किरोड़ी मीणा ने किशनगढ़ की निम्नलिखित 12 फैक्ट्रियों में जांच की थीः अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कमला बायो ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राघव एग्रो इंडस्ट्रीज श्री गोवर्धन एग्रो दिव्या एग्रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, नालू भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज श्रीनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज एशिया डोन बायोकेयर, जयपुर वर्दी जल एग्री टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अजमेर 11-12. अन्य दो फैक्ट्रियों का भी निरीक्षण किया गया। अब कृषि विभाग इन फैक्ट्रियों के मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।

NEET UG-2024 फर्जीवाड़ाः जोधपुर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के छात्रों से CBI की पूछताछ, डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने का शक

24 न्यूज अपडेट

वीसी बोले – गड़बड़ी को लेकर हो रही गंभीर जांच, 10-12 छात्रों की पहचान और दस्तावेज खंगाले जोधपुर, 29 मई। NEET UG-2024 परीक्षा में फर्जीवाड़े की जांच अब राजस्थान के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने जोधपुर स्थित डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीते चार दिनों से डेरा डाल रखा है। सूत्रों के अनुसार, यहां द्वितीय और तृतीय वर्ष के करीब 10-12 छात्रों से पूछताछ की जा रही है। CBI को शक है कि इन छात्रों ने डमी कैंडिडेट बनकर अन्य अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास किया। इस सिलसिले में CBI ने फोटो, हस्ताक्षर और तकनीकी साक्ष्यों का मिलान कर जांच तेज कर दी है। बिहार में पकड़े गए गैंग से खुलासा, जोधपुर तक जुड़े तार पटना से शुरू हुई इस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब जोधपुर AIIMS के MBBS तृतीय वर्ष के छात्र हुकमाराम गोदारा को 4 लाख रुपए लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएवी स्कूल परीक्षा केंद्र में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने की कोशिश करते पकड़ा गया। वह प्रयागराज निवासी डॉक्टर आर.के. पांडे के बेटे राज पांडे की जगह परीक्षा देने गया था, लेकिन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में फेल हो गया और धर दबोचा गया। इस प्रकरण से जुड़े CBI के केस (FIR) की जांच दिल्ली की स्पेशल यूनिट कर रही है। तकनीकी जांच के जरिए छात्रों के अकादमिक रिकॉर्ड, परीक्षा केंद्रों के CCTV, बायोमेट्रिक डेटा और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है। कुलपति ने दी पुष्टि, सीबीआई की जांच जारी इस पूरे मामले में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रदीप कुमार प्रजापति ने कहा कि – "CBI की टीम NEET UG में गड़बड़ी को लेकर जांच कर रही है। जांच में जिन गैंग के सदस्य पकड़े गए हैं, उनसे मिली जानकारी के आधार पर हमारे विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों की संलिप्तता की आशंका है। फिलहाल टीम जांच कर रही है और हम उन्हें पूरा सहयोग दे रहे हैं।" CBI की जांच पूरी होने के बाद यदि डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने की पुष्टि होती है, तो छात्रों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और परीक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई संभव है। साथ ही संबंधित संस्थानों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।

खाओ-खिलाओ संस्कृति में पड़ी खलल, सावधानी हटी, रिश्वत की दुर्घटना घटी : सीडीपीओ में लेखाधिकारी नूतन पंड्या रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, सात माह का वेतन पास कराने की बदले मात्र 9 हजार की मांगी रिश्वत

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। रिश्वत लेते पकड़े जाना अब आम हो गया है। सिस्टम के बड़े हाथी सिंडिकेट बना कर इतनी बारीकी से लूट मचाते हैं कि कभी नहीं पकड़े जाते तो कभी कभार सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की तर्ज पर छोटे मोटे अमाउंट के लालच में रिश्वत के जाल में छोटी मोटी सरकारी मछलियां फंस जाती है। मजे की बात है कि खाओ खिलाओ संस्कृति के आदि हो चुके हमारे सिस्टम में जब रिश्वत का लेन देने सार्वजनिक उपहास व प्रताड़ना का विषय नहीं होता। सबको पता है कि मामले सेटल होते हैं व कई बार से सरकारी स्तर पर ही अभियोग के अनुमति नहीं दी जाती। ताजा मामला उदयपुर से है जहां पर आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर की टीम ने महिला एवं बाल विकास विभाग के गोगुंदा स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय याने की सीडीपीओ ऑफिस की लेखाधिकारी नूतन पंड्या को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उन्होंने दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सात माह से लंबित वेतन पास कराने के नाम पर मांगी थी। एसीबी एडीएसपी अनंत कुमार ने मीडिया से कहा कि पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उदयपुर एसीबी कार्यालय में शिकायत दी कि अक्टूबर 2023 से वेतन नहीं मिला है। जब उन्होंने गोगुंदा स्थित सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लेखाधिकारी नूतन पंड्या से संपर्क किया, तो उसने प्रत्येक से 4500 रुपये, कुल 9 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की। शिकायत के अनुसार, 23 मई को नूतन पंड्या ने दोनों से 2,000-2,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये पहले ही ले लिए थे, और बकाया 5,000 रुपये के लिए बार-बार दबाव बना रही थी। शिकायत की पुष्टि के बाद, एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई। आज जब पीड़ित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने गोगुंदा सीडीपीओ कार्यालय में लेखाधिकारी नूतन पंड्या को शेष 5,000 रुपये रिश्वत दिए, उसी वक्त एसीबी टीम ने छापा मारकर उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी इंस्पेक्टर नरपत सिंह के नेतृत्व में की गई इस ट्रैप कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि लेखाधिकारी के पास से बरामद कर ली गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया। इस गिरफ्तारी से महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, लेखाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान के नाम पर रिश्वत वसूली की यह कोई पहली घटना नहीं है, और विभागीय भुगतान से जुड़े अन्य मामलों की भी जांच शुरू हो सकती है।

राजस्थान में भेड़ निष्क्रमण के लिए पुख्ता इंतजाम, 8.15 लाख भेड़ें और 14,965 पशुपालकों की संभावित आवाजाही के मद्देनज़र मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

24 न्यूज अपडेट

जयपुर, 30 मई। राज्य में आगामी भेड़ निष्क्रमण वर्ष 2025-26 के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। शासन सचिवालय में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भेड़ निष्क्रमण को निर्बाध, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

भेड़पालकों और किसानों के बीच टकराव की रोकथाम पर विशेष ज़ोर

मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार भेड़ें किसानों के खेतों में घुस जाती हैं जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क रहकर संवेदनशील क्षेत्रों में पुख्ता इंतजाम करें, ताकि किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या न हो। उन्होंने भेड़पालकों को निर्धारित मार्गों से ही निष्क्रमण कराने और मार्ग परिवर्तन की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

चैकपोस्ट, टोलियां और पंजीकरण की व्यवस्था को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

श्री पंत ने संबंधित विभागों को कहा कि निष्क्रमण के एन्ट्री प्वाइंट चिन्हित करते हुए 191 चैकपोस्टों की स्थापना, आवश्यक कार्मिकों की नियुक्ति, स्थायी-अस्थायी जांच चौकियां एवं संवेदनशील स्थानों पर समन्वित भ्रमण टोलियां गठित करना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, भेड़पालकों के पंजीकरण, परिचय पत्र जारी करने, भेड़ों के लिए दवाओं और टीकों की व्यवस्था, तथा अस्थायी टेंट, शेड, राशन व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए।

पशुपालन विभाग ने दी विस्तृत जानकारी

बैठक में पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि राज्य में हर वर्ष चारे की उपलब्धता के लिए लाखों की संख्या में भेड़ें और हजारों भेड़पालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर निष्क्रमण करते हैं। पिछले वर्ष 8.15 लाख भेड़ें और 14,965 पशुपालक राज्य में निष्क्रमण के लिए आए थे। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में भेड़पालकों के आने की संभावना है जिसके लिए भेड़ों के लिए वैक्सीन, दवाइयों और चारा आदि की समुचित व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि वर्षा शुरू होते ही भेड़पालक राज्य के पठारी क्षेत्रों की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। राज्य स्तरीय समन्वय और जिला स्तर पर निगरानी के निर्देश मुख्य सचिव ने कहा कि संभागीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के कलेक्टरों व पशुपालन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं सुचारू करें। इस दौरान सभी संबंधित विभागों के सचिव, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे।

राजस्थान माइनिंग सेक्टर में देशभर में अव्वल, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में निजी सहभागिता को मिल रहा प्रोत्साहन

केंद्रीय खान सचिव वी.एल. कांताराव ने जयपुर में की राज्य की प्रगति की सराहना

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। देश में खनिज संसाधनों की खोज, दोहन और पुनः उपयोग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों के बीच राजस्थान माइनिंग सेक्टर में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। केंद्रीय खान सचिव श्री वी.एल. कांताराव ने शुक्रवार को जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि "माइनिंग सेक्टर में राजस्थान सबसे प्रगतिशील राज्य है। मेजर मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन में भी यह देश में सबसे आगे है।"

निजी एक्सप्लोरेशन एजेंसियों को मिल रहा प्रोत्साहन

श्री कांताराव ने बताया कि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (NMET) के अंतर्गत देशभर में अब तक 35 प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसियों को पंजीकृत किया जा चुका है, जिनमें से 20 ने राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में कार्य आरंभ कर दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार अब एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग तक निजी सहभागिता को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि माइनिंग सेक्टर को तकनीकी रूप से और सशक्त बनाया जा सके। क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग, केंद्र सरकार की प्राथमिकता कांताराव ने कहा कि देश और वैश्विक स्तर पर क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना के साथ अब केंद्र सरकार इस दिशा में अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रोसेसिंग और रिसाइक्लिंग को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने जानकारी दी कि एनएमईटी के फंड से NPEA (National Private Exploration Agencies) को सहयोग, प्रोसेसिंग के लिए R&D फंड और रिसाइक्लिंग कंपनियों को इंसेंटिव देने की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

राजस्थान ने बनाए नए रिकॉर्ड

राजस्थान के शासन सचिव, खान विभाग श्री टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य में अब तक 88 मेजर मिनरल ब्लॉक्स का सफल ऑक्शन किया जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में नई खनिज नीति, एम-सैंड नीति और नियमों के सरलीकरण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान योजनाबद्ध रूप से माइनिंग सेक्टर को मजबूती दे रहा है।

खानधारकों और प्रतिनिधियों से संवाद

इस बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों, माइनिंग एसोसिएशनों, खानधारकों, एलओआई धारकों, जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम, डीजीएमएस तथा अन्य विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी पक्षों के बीच सीधे संवाद और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान पर बल दिया गया। नीमकाथाना विधायक श्री सुरेश मोदी ने माइनिंग सेक्टर से जुड़ी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की मांग उठाई, जबकि माइनिंग एसोसिएशन ने माइनिंग को उद्योग का दर्जा, बीमार खनन पट्टों को पुनर्जीवित करना, डीएमएफटी फंड का स्थानीय उपयोग, लैंड बैंक की स्थापना और छोटे खानधारकों की समस्याएं हल करने जैसे सुझाव दिए।

निर्देशित हुए सेमिनार-वर्कशॉप

केंद्रीय सचिव ने जीएसआई, एमईसीएल, आईबीएम, डीजीएमएस और राज्यों के वन एवं पर्यावरण विभागों को निर्देश दिए कि माइनिंग सेक्टर में कार्यरत सभी पक्षों को नए नियमों और अवसरों की जानकारी देने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए जाएं।

महत्वपूर्ण उपस्थिति- इस मौके पर खान निदेशक श्री दीपक तंवर ने पीपीटी प्रजेंटेशन के जरिए राजस्थान की प्रगति और ऑक्शन ब्लॉकों की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा केंद्रीय उप सचिव डॉ. आशीष सक्सेना, नोडल अधिकारी श्री अरुण प्रसाद, सिया के सचिव श्री विजय एन, जीएसआई के अनिंद्य भट्टाचार्य, एमईसीएल के श्री इन्द्रदेव नारायण, आईबीएम के श्री चंद्रेश बोहरा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

डॉ. लक्ष्मीनारायण मीणा संभागीय अतिरिक्त निदेशक व डॉ. सुरेश जैन जिला संयुक्त निदेशक नियुक्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 30 मई। राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में प्रशासनिक स्तर पर महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए डॉ. लक्ष्मीनारायण मीणा को उदयपुर संभाग का संभागीय अतिरिक्त निदेशक एवं डॉ. सुरेश जैन को जिला संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है। दोनों अधिकारियों ने शुक्रवार को अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। कार्यक्रमों की धीमी प्रगति के कारण बदली जिम्मेदारियाँ मेवाड़ पशुचिकित्सक संघ के संरक्षक डॉ. दिनेश चन्द्र सारड़ा ने बताया कि खुरपका-मुंहपका रोग टीकाकरण अभियान और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की सुस्त प्रगति को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि कार्यक्रमों को गति दी जा सके और निर्धारित लक्ष्यों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सहयोग की अपील- पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. मीणा और डॉ. जैन ने मेवाड़ पशुचिकित्सक संघ एवं तकनीकी कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात कर आग्रह किया कि राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने खुरपका-मुंहपका टीकाकरण और पशु बीमा योजना के 100 प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति का संकल्प भी दोहराया। पदभार ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे अधिकारी इस अवसर पर मेवाड़ पशुचिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ. शैलेन्द्र शुक्ला, डॉ. रविन्द्र गोयल, डॉ. मुकेश नागौरी, डॉ. कृष्णगोपाल नामा, डॉ. महेन्द्र मेहता, डॉ. ओमप्रकाश साहू, डॉ. सुरेन्द्र छगानी, डॉ. लज्जाराम मीणा, डॉ. सुरेश शर्मा, डॉ. राजकिशोर बंसल, डॉ. केदार वैष्णव, डॉ. विजय माने, डॉ. सविता मीणा, डॉ. पदमा मील सहित कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि कालूलाल पटेल, गिरधारीलाल तिवारी और मंशाराम उपस्थित रहे।

एमबी चिकित्सालय में जयपुर से आई विशेष टीम ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर हुई चर्चा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। संभाग के सबसे बड़े राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय (एमबी हॉस्पिटल) की व्यवस्थाओं का जायजा लेने शुक्रवार को जयपुर से एक विशेष टीम उदयपुर पहुंची। टीम ने अस्पताल परिसर का भ्रमण कर विभिन्न विभागों की स्वास्थ्य सेवाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। जांच के दौरान एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन भी मौजूद रहे। उन्होंने टीम को अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों, नवीन योजनाओं और अधूरी परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने मौजूदा समस्याओं को भी टीम के समक्ष रखा और उनके समाधान के लिए प्रस्तावित आगामी योजनाओं से अवगत कराया। टीम से जुड़े मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों से चर्चा कर उन्हें व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन ने कहा: "जयपुर से आई विशेष टीम को एमबी चिकित्सालय में चल रहे समग्र विकास कार्यों, नई सुविधाओं के विस्तार और संसाधनों की स्थिति से अवगत कराया गया। उम्मीद है कि टीम की सिफारिशों से अस्पताल की व्यवस्थाएं और अधिक मजबूत होंगी।"

गृह जिलों में ग्रीष्मावकाश मना रहे शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी से किया जाए मुक्तः शिक्षक संघ की मांग

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर. राजस्थान में ग्रीष्मावकाश के दौरान आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर एक गंभीर मांग सामने आई है। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों से आग्रह किया है कि अपने गृह जिलों में अवकाश पर गए शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। प्रदेशाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और राज्य लोक सेवा आयोग की कई परीक्षाएं जून माह में प्रस्तावित हैं। इसी दौरान शिक्षकों को वार्षिक ग्रीष्मावकाश भी मिला है, जिसके चलते हजारों शिक्षक अपने-अपने मूल निवास स्थान पर गए हुए हैं।

पदस्थापन और गृह जिला के बीच लंबी दूरी

संघ का कहना है कि कई शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से 500 से 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में परीक्षा ड्यूटी में शामिल होने के लिए उन्हें बार-बार मुख्यालय लौटना पड़ता है, जो मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कष्टप्रद है। शिक्षक संघ ने यह भी बताया कि ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय छोड़ने की विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बावजूद, विभागीय समन्वय की कमी के कारण इन शिक्षकों को परीक्षा ड्यूटी के आदेश थमा दिए जाते हैं। परिवार और दायित्वों के बीच संघर्ष शेरसिंह चौहान ने कहा, "एक ओर शिक्षक अपने परिवार के साथ सीमित अवकाश के समय को व्यतीत करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर बार-बार परीक्षा ड्यूटी के कारण उन्हें मानसिक तनाव और यात्रा की परेशानी झेलनी पड़ रही है। यह न केवल शिक्षकों के हित में अनुचित है, बल्कि प्रशासनिक असंगतियों को भी दर्शाता है।" संघ ने मांग की है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति उनके गृह जिले से दूर है और जो ग्रीष्मावकाश में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर गए हैं, उन्हें परीक्षा ड्यूटी से छूट दी जाए। इससे न केवल शिक्षक तनावमुक्त होकर अवकाश मना सकेंगे, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी और मानवीय हो सकेगी।

चौधरी स्मृति कुश्ती दंगल में चतुर्भुज हनुमान व्यायामशाला के पहलवानों का जलवा, तीन खिताब किए अपने नाम

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। हाल ही में आयोजित चौधरी स्मृति कुश्ती दंगल में श्री चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला के पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन खिताब अपने नाम किए। व्यायामशाला के कोच हेमंत अठवाल ने बताया कि अखाड़े के पहलवानों ने ना केवल दमदार कुश्ती लड़ी बल्कि तकनीकी कौशल से अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी। पलक सोनी ने 50 किलोग्राम भारवर्ग में वंशिका कलाल को बाय फाल चित्त कर 'उदयपुर बाल पद्मिनी' का खिताब जीता। राजीव ओड ने दक्ष मोदी पर तकनीकी सिपेरियोरिटी के आधार पर 10-0 से विजयी होकर 'उदयपुर बाल बसंत' का टाइटल अपने नाम किया। अंकित ओड ने फाइनल में मेजबान अखाड़े के सुरेंद्र को निकाल दांव लगाकर बाय फाल से परास्त कर 'उदयपुर वीर लव' का खिताब जीता। व्यायामशाला संचालक कृष सेन ने बताया कि अन्य पहलवानों ने भी दंगल में शानदार प्रदर्शन किया— पंकज ओड, राकेश सिसोदिया, मनीष नटवंश और नंदिनी जोशी ने फाइनल तक पहुंचकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। माही ओड और अजय ओड ने अपने-अपने भारवर्ग में तृतीय स्थान हासिल किया। व्यायामशाला की इस सफलता पर अध्यक्ष विरामदेव सिंह कृष्णावत ने सभी विजेता और उपविजेता पहलवानों को बधाई दी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय कोच रेफरी कैलाश पालीवाल, राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता राकेश अटवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा, हरीश यादव, सुंदर सोलंकी, दिलीप कल्याणा, लोकेश कुमावत, दीपक मोदी, सुजल मोदी, किशोर मल्होत्रा, केशुलाल भील, हिरल मोदी, सुरेंद्र सिंह चौहान, विक्की पठुन और दीपक वसीटा सहित कई गणमान्य सदस्यों ने पहलवानों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

1 जून को गोवर्धन सागर पाल पर होगा योग का पूर्वाभ्यास" - डॉ. शोभालाल औदीच्य

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। उदयपुर जिले को निरोग और स्वस्थ बनाने की दिशा में पतंजलि योग परिवार उदयपुर द्वारा वीरवाल जैन समाज छात्रावास, मनवाखेड़ा में इंटीग्रेटेड सह-योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 18 मई 2025 से सतत रूप से किया जा रहा है। संवाद प्रभारी योग साधक श्री जिग्नेश शर्मा ने बताया कि शिविर के अंतर्गत जिला स्तरीय कॉमन योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास वरिष्ठ योगाचार्य श्री गणपत लाल चितारा के निर्देशन में किया गया। इस पूर्वाभ्यास में प्रार्थना, वार्मअप, सूक्ष्म व्यायाम, खड़े, बैठे, पीठ एवं पेट के बल किए जाने वाले आसनों के साथ-साथ प्राणायाम व योगनिद्रा का अभ्यास कराया गया। योग सूत्रों की व्याख्या और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी श्री मुकेश पाठक ने अष्टांग योग और योग सूत्र पर गूढ़ एवं सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत की। इस अवसर पर आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक एवं नोडल अधिकारी डॉ. राजीव भट्ट ने जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियों के तहत जिला स्तरीय योग प्रोटोकॉल का मिनट-टू-मिनट पूर्वाभ्यास 20 जून तक जिले के विभिन्न ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों पर आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला समन्वयक व अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री वार सिंह ने योग को अपनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, "नियमित योगाभ्यास न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अनिवार्य है।" उन्होंने नागरिकों से योग सत्रों में अधिकाधिक भागीदारी करने का आग्रह किया।

24 न्यूज अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।